

UPGK010077602025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**सेशन केस संख्या- 1831/2025**

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामेश्वर दूबे आदि

अपराध संख्या- 816/2024,

धारा- 103(1), 115(2), 352, 351(3), 126(2),

109, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता

थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर।

11.05.2026

1. सत्र परीक्षण की पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना-पत्र कागज संख्या-17ख अंतर्गत धारा-250 भा०ना०सु०सं० पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 17ख के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या- 816/2024, धारा- 115(2), 352, 351(3), 126(2), 103(1), 109, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

3. प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 17ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि "प्रार्थी उपरोक्त मामले में पूर्णतया: निर्दोष है, उसका उपरोक्त मामले से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से वादी मुकदमा एवं पुलिस द्वारा मामले उपरोक्त में रंजिशन फंसा दिया गया है जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण अवलोकन एवं परिशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत तहरीर में कथित वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध स्पष्ट रूप से केवल यह आरोप लगाया गया है कि उक्त कथित घटना के पीछे प्रार्थी का पूर्ण रूप से हाथ है जिसमें एक षड्यंत्र रचते हुए अपने सहयोगियों की मदद से वादिनी मुकदमा के ससुर की हत्या करवा दिया है लेकिन कदापि रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थी किस प्रकार षड्यंत्र रचा था तथा उक्त षड्यंत्र को किसी तीसरे व्यक्ति ने किसी प्रकार से अपने आखों से देखा व षड्यंत्र रचते हुए सुना था जिससे भी प्रश्नगत

अभियोजन कथानक प्रार्थी के विरुद्ध केवल मिथ्या, मनगढ़ंत, काल्पनिक व संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रश्नगत मामले की वास्तविकता यह है कि कथित घटना के 15 दिन पूर्व से ही प्रार्थी अपनी जीविकोपार्जन स्थल से 1700 किलोमीटर दूर गुजरात प्रदेश में कार्यरत था तथा कथित घटना के समय न तो भौतिक रूप से घटना स्थल पर उपस्थित था और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर उपस्थित था और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित घटना में शामिल रहा है और न ही दौरान विवेचना पुलिस/विवेचक के पास कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य ही उपलब्ध है जिससे प्रार्थी कथित अपराध में संलिप्तता प्रमाणित होती है। पत्रवाली के समग्र अवलोकन से भी यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी को मामले में केवल षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है जबकि यह धारा 61(2) BNS को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक विधिक तथ्य है कि षड्यंत्र के पूर्ण दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में Meet Of Mind होना चाहिए तथा उक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत अपराध कारित होने चाहिये" लेकिन प्रश्नगत मामले में सम्पूर्ण अभियोजन में यह कदापि रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है कि प्रार्थी किस प्रकार से उक्त अपराध का षड्यंत्र रचा था जिससे प्रार्थी के विरुद्ध अधिरोपित धारा 61(2) BNS का अपराध गठित नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकरण की वास्तविकता यह है कि मामले में कथित मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को केवल हाथ व पैर में चोटें आयी हैं तथा मृतक के वाईटल पार्ट में कोई भी चोटें कारित नहीं हुयी थी तथा डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा प्रिजर्व किया गया है, जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले के मृतक की मृत्यु अभियोजन कथानक के अनुसार लाठी, डंडे व हॉकी से कारित की गयी, चोट से नहीं हुयी है, बल्कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे भी प्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत अभियोजन कथानक पूर्णतः मिथ्या, मनगढ़ंत, काल्पनिक व संदेहास्पद प्रतीत होता है। जिस कारण पर प्रार्थी प्रश्नगत आरोप से उन्मोचित किये जाने योग्य है। वास्तविकता यह है कि मृतक कथित घटना दिनांक को मोटर साइकिल से कहीं जा रहा था कि तभी घटना स्थल पर काफी घना कोहरा होने के कारण पीछे से किसी अज्ञात 1 वाहन चालक से ठोकर लग जाने के कारण मोटर साइकिल सहित सड़क पर गिर गये, जिससे मृतक के हाथ व पैर में एक ही साईड में चोटें आयी तथा अत्यधिक ठंड व वृद्धा अवस्था के कारण कोमा में चले जाने से मृतक की मृत्यु हो गयी। मृतक के मृत्यु की इस विशिष्ट कारण के आधार पर भी प्रार्थी को प्रश्नगत आरोप से उन्मोचित किया जाना न्याय संगत है। प्रश्नगत मामले की वास्तविकता यह भी है कि मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों से पुरानी रंजिश के कारण वादिनी मुदकमा ने मृतक की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु का लाभ उठाते हुए एक फर्जी विशुद्ध व बनावटी व भ्रामक तथा मंगढ़नत एवं काल्पनिक कथानक के आधार पर प्रश्नगत मुकदमा दर्ज करा दी है तथा वादिनी ने पुलिस की मिलीभगत से प्रार्थी का नाम बिना किसी ठोस व प्रमाणिक साक्ष्य के सरसरी तौर पर शामिल कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी की प्रश्नगत मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता कदापि रूप से नहीं रही है। कथित घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक ने प्रार्थी के पिता को लाठी, डंडे से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में मृतक के विरुद्ध थाना गोला में Cr.No- 770/2024 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351 (3), 110

BNS मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस के डर से व घर से भागा हुआ था तथा एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण व पुरानी रंजिश के कारण प्रार्थी के विरुद्ध उक्त मुकदमा विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज करा दिया गया है। जबकि प्रार्थी की संलिप्तता के बावत अभियोजन के पास दौरान सम्पूर्ण विवेचना कोई ऐसा साक्ष्य ही मौजूद पाया गया है जिससे प्रार्थी की मामले में संलिप्तता प्रमाणित हो सके। इस प्रकार प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्यक अवलोकन व परिशीलन एवं उपरोक्त विधिक तथ्यों एवं परिस्थितियों व सम्पूर्ण अभियोजन कथानक व मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी विरोधाभास होने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों की प्रकृति, मृत्यु का कारण व सम्पूर्ण विवेचना में विवेचक द्वारा एकत्र किये गये प्रश्नगत पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कादापी रूप से मृतक की मृत्यु कारित नहीं की गयी है और न ही प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना में शामिल रहा है तथा न ही मृतक की कथित मृत्यु उसके शरीर में आयी चोटों से हुयी है जिस आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध धारा 115 (2), 352, 351(3) 126(2), 103(1), 109 BNS का अपराध गठित नहीं होता है तथा प्रार्थी उपरोक्त धाराओं से उन्मोचित किये जाने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियोजन पक्ष द्वारा संकलित समस्त अभियोजन साक्ष्यों, बयानात वादी स्वतंत्र गवाहों, निरीक्षण घटना स्थल मृतक के शरीर पर आयी चोटों के मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत पत्रवाली में प्रथम दृष्टया कोई भी कथित अपराध प्रमाणित नहीं होता है बावजूद इसके प्रार्थी को राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के कारण उक्त मुकदमें में फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाकर सरसरी तौर पर मनगढ़ंत एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध पुलिस द्वारा वादिनी मुकदमा की मिली भगत से सरसरी तौर पर दूषित विवेचना करते हुए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण प्रार्थी उपरोक्त सभी धाराओं से उन्मोचित किये जाने योग्य है। उपरोक्त विधिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रश्नगत पत्रावली में प्रार्थी के विरुद्ध आरोप विरचन किये जाने हेतु सम्यक साक्ष्य न उपलब्ध होने एवं इस स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त विधिक आधार न होने के कारण प्रार्थी को मामले उपरोक्त से उन्मोचित किया जाना न्यायसंगत है।" इस प्रकार प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 17ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र कागज संख्या-17ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 13.12.2024 को, अन्तर्गत थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें आवेदक/अभियुक्त के इशारे पर सह-अभियुक्तगण के द्वारा प्रथम सूचनाकर्त्ती गुड़िया दूबे को लोहे की राड से मारने व जान से मारने की धमकी तथा उसके ससुर झिनकू दूबे के ऊपर भी लोहे के राड व हाकी-डण्डा से मारकर गम्भीर उपहति कारित करते हुए उनकी मृत्यु कारित करने का कथन किया गया था।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 13.12.2024 को समय 21.49 बजे, अभियुक्तगण तारकेश्वर दूबे, परमेश्वर दूबे, रामेश्वर दूबे, लक्ष्मीकान्त उर्फ सोनू दूबे व दो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध संख्या- 816/2024, धारा- 115(2), 352, 351(3), 126(2), 103(1), 109, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गोला, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया, घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया, समयी साक्षीगण का बयान अंकित किया गया एवं विवेचना की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 115(2), 352, 351(3), 126(2), 103(1), 109, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 10.03.2025 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकार्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लिए गए संज्ञान आदेश दिनांकित 10.03.2025 को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई।

8. विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं०-2 में वादिनी मुकदमा गुड़िया दूबे पत्नी अभय दूबे का बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया है कि- दिनांक 13.12.2024 को समय 06.30 बजे सुबह मैं अपने ससुर स्व० झिनकू दूबे के साथ मोटर साइकिल से गोरखपुर कोर्ट में बयान देने हेतु जा रही थी। जब हम लोग गोला कौड़ीराम रोड पर देवकली पेट्रोल पम्प के पास पहुँचने वाले थे तभी पीछे से चार पहिया सफेद स्कार्पियो वाहन UP32DY1818 जो रामेश्वर दूबे की है, इसी गाड़ी से तारकेश्वर दूबे व परमेश्वर दूबे पुत्रगण विजयशंकर दूबे तथा दो अज्ञात व्यक्ति जो मुँह पर कपडा बाँधे हुए थे, हमलोगों को जान से मारने की नियत से हमारी मोटर साइकिल में पीछे से ठोकर मार दिये जिससे मेरे ससुर जो कि गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी लड़खड़ायी लेकिन हम लोग गिरने से बच गये। मेरे ससुर ने मोटर साइकिल को सड़क के किनारे रोक लिया तभी स्कार्पियो सवार उपरोक्त विपक्षीगण स्कार्पियो रोककर तथा स्कार्पियो में से लोहे का राड, हाकी व डण्डा

लेकर उतरे और गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे ससुर को व मुझे जान से मारने की नियत से एक राय होकर बुरी तरह लोहे के राड, हाकी व डण्डा से मारने लगे। मेरे ससुर ने अपने बचाव का भरसक प्रयास किया लेकिन विपक्षीगण के मारने-पीटने से उनके हाथ-पैर कई जगह से टूट गये और वह जमीन पर गिर पड़े, फिर मैंने शोर मचाने का प्रयास किया तो विपक्षीगण ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। मेरे ससुर की मोटरसाइकिल विपक्षीगण के स्कार्पियो गाड़ी के सामने गिर गयी थी राहगीरों को इकट्ठा होता देख विपक्षीगण जब अपनी स्कार्पियो गाड़ी में बैठकर कौड़ीराम की तरफ भागने लगे तो मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी में फँस गयी जिसे मुँह पर गमछा बाँधे व्यक्ति ने स्कार्पियो से उतरकर हटाया लेकिन इस दौरान उसके मुँह पर बधा गमछा खुल गया जिसपर मैंने उसे पहचान लिया उपरोक्त व्यक्ति का नाम रविन्द्र यादव उर्फ पवन यादव पुत्र स्व० दुर्गा प्रसाद यादव जो ग्राम अहिरौली प्रथम थाना गोला जनपद गोरखपुर का रहने वाला है तथा अक्सर परमेश्वर दूबे, रामेश्वर दूबे व तारकेश्वर नाथ नाथ दूबे के साथ घूमता रहता है। फिर ये तीनों परमेश्वर दूबे, तारकेश्वरनाथ दूबे, पवन उर्फ रविन्द्र यादव व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति जिसे मुँह पर गमछा बंधा होने के कारण मैं पहचान नहीं पायी थी ये सभी लोग अपनी स्कार्पियो गाड़ी से कौड़ीराम की तरफ भाग गये।

9. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्य के बाबत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है, वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर तक मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला देखा जाना होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

10. यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण-दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं। जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा- 115(2), 352, 351(3), 126(2), 103(1), 109, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। अतएव, आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

11. आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेंट एण्ड रिमेंब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरुद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी०) में यह

अवधारित किया है कि— “At this stage, as was pointed out by this Court in *State of Bihar v. Ramesh Singh*’ AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence.”

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ़ एम०पी० विरुद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665) में यह अवधारित किया गया है

कि— “It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed.”

13. इसी प्रकार दाण्डिक अपील संख्या-1578/2008 संघी ब्रदर्थ (इंदौर) प्रा०लि० बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008 के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा-11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि—

“The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed.”

14. विधि व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरुद्ध मामला बनता है अर्थात् यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है,

किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

15. पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- “Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time.”

16. अतएव, सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर दुबे को अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है।

17. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर दुबे की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कागज संख्या-17ख निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र के निस्तारण में जो भी संप्रेक्षण दिये गये हैं वे मात्र इस प्रार्थना पत्र तक ही सीमित होंगे। इनका कोई प्रभाव मामले के गुण-दोष पर नहीं पड़ेगा।

आदेश

18. आवेदक/अभियुक्त रामेश्वर दुबे द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 17ख निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त आरोप की विरचना हेतु दिनांक 29.05.2026 को पेश हो। आवेदक/अभियुक्त नियत तिथि को अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिनांक/गोरखपुर
11 मई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889